

श्री सत्यपाल मलिक : माननीय मंत्री जी से मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि आपके मंत्रालय ने विस्कों, जो मैचेज बनाने की एक विदेशी कम्पनी है, उस को स्वीडन की एक फर्म से टैक्निकल नौहाऊ इम्पोर्ट करने की इजाजत देने का फैसला किया है। क्या इस मामले में वित्त मंत्रालय और आपके मंत्रालय में कोई मतभेद है ?

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sir, I require notice for this specific question.

MR. CHAIRMAN: Question No. 45.

Declaration of Purva Anchal As Backward Area

*45. **SHRI SYED AHMAD HASHMI:** Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the PURVA ANCHAL (Eastern U.P.) comprising ten districts has been declared backward area;

(b) if so, what steps Government propose to take during the Sixth Five Year Plan period for the speedy development of the said area; and

(c) what will be the total financial allocation section-wise in the Sixth Five Year Plan for this area?

THE MINISTER OF PLANNING AND LABOUR (SHRI NARAYAN DUTT TIWARI): (a) The State Government have included in the Eastern Region 15 districts of which 10 have been identified as industrially backward districts qualifying for concessional finance from institutions.

(b) and (c) Outlays for the Sixth Five Year Plan of the State have been approved under major sectors of development on the basis of proposals made by the State Government. Dis-aggregation of these outlays for regions/area/districts within the State is done by the State Government.

श्री संयद अहमद हाशमी : जनाव सद्र, यह सवाल हमदर्दी का भी है, इंसाफ का भी है। हमारे मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। टैक्निकल जबाब दे देना बहुत आसान है, और टैक्निकल जबाब मिल गया, लेकिन इस से जाहिर है कि हमारा या उत्तर प्रदेश या खस्सन पूर्वांचल के लोगों को इत्मीनान हो नहीं सकता। बहुत मामूली सी मिसाल है कि अगर कहीं भारी वारिश आई तो सैलाब की तबाहीकारी से वह परेशान और उनका मकान और जरायती जिदगी का कोई अशिया बाकी नहीं रहता, और अगर सूखा पड़े तो वह कहतकारी का शिका एक-एक दाने से वह मोहताज।

मान्यवर, हिन्दुस्तान की आजादी के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिक हिस्सों ने से हिस्सा लिया। उसमें यू० पी० पीछे नहीं हा। और पूर्वांचल ना वह हिस्सा है जिसने देश की आजादी के लिए बड़ी अहम कुर्बानी दी है, लेकिन उस के बावजूद मैं कहूँगा कि आजादी के इन तीस वर्षों में वह डिस्ट्रीमिनेशन और इस्तीयाज का शिकार है और मरकजी हुकूमत इस की जिम्मेदार हैं। मैं एक उदाहरण दू—गाजीपुर पूर्वांचल का बह जिला है जिसमें सन् 1942 के जमाने में यूनियन जैक को उतार कर फैक दिया और आजादी का परचम लहराया, लेकिन वहाँ की दशा यह है कि वहाँ के लज्जावाले आज भी, इस सदी में इस ज़माने को पहुँच गये हैं कि वह जानवर, मैंग और गाय जो लीद कर देती है उस के अन्दर से दाना चुन कर और उसे धोंयन खाते हैं। वह गरोबी की उस रेखा वा पहुँच चुके हैं इसलिए कि वहाँ न कोई इंडस्ट्री है न और कुछ। बावजूद यह बात के कि मरकजी हुकूमत ने डिक्टेयर

किया है... (समय की घंटी) मैं सवाल कर रहा हूँ। (ध्यवधान)

श्री सभापति : सवाल नहीं कर रहे हैं, लैक्चर दे रहे हैं।

श्री रामेश्वर सिह : श्रीमन्, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गरीब इलाके के रहने वाले हैं, इसलिए ये लोग हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि यह नहीं चाहते कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को कुछ मिले।

श्री संयद अहमद हाशमी : मैं सवाल कर रहा हूँ। यू० पी० के पूर्वांचल के कुछ जिलों को आपने बैकवर्ड और पसमादा करार दिया है। मैं कहता हूँ कि पूरे के पूरे पूर्वांचल को बैकवर्ड करार देना चाहिए। मैंने आपके सामने खा कि गाजीपुर जिला गरीबी की फिस सीमा को पहुँच चुका है, लेकिन उन जिलों के अन्दर गाजीपुर को शामिल नहीं किया गया। इस के बारे में क्या विचार है?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जनाव मैं मोहतरीम मैम्बर के ख्यालात की बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्होंने यह फरमाया कि मरकजी हुकूमत ने इस तरफ गौर नहीं किया है। मैं उनसे यह अर्ज करना फर्ज समझता हूँ कि अगर जो आंकड़े हैं, जो वहाँ के हालात हैं, जो कुछ पिछले मंसूबों के दौरान किया गया है, उन की ओर वे गौर फरमायें तो उन्हें इस बात का तस्कीन होगा कि जो इस बीच किया गया है वह भले ही नाकाफी हो फिर भी ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं उनकी तवज्ज्ञह खास तौर पर दिलाना चाहूँगा शारदा सहायक योजना की ओर जो हमारे मुल्क के सब से बड़े सिचाई के मंसूबों में से है और जिसके द्वारा 40 लाख एकड़ सिचित जमीन में

गाजीपुर, बनारस, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद बगैर जिले पूर्वी यू० पी० के शामिल हैं। यह इतनी बड़ी स्कीम है कि उस में पांच पानी हर खेत को मिलने का इमकान है। इसी तरह गाजीपुर में देवकली पंप कैनाल है। देवकली नहर का पहला मंसूबा पूरा हो चुका है, दूसरा मंसूबा हो रहा है। गाजीपुर में एक बड़ा पुल गंगा पर बनाया जा रहा है। वहाँ नन्दगंज की चीनी मिल है। ऐसा नहीं है कि कोई तवज्ज्ञह नहीं दी गई है।

मैं यह भी अर्ज कहूँगा मोहतरीम मैम्बर से कि यू० पी० का जो छठा मंसूबा है वह 6200 का अभी हाल ही में तय हुआ है और सूबाई सरकार इस बारे में इन्तहा गौर फरमा रही है। हर जिले की स्कीम बन रही है और कारपोरेशन अलग डिवीजनों के बन रहे हैं। बनारस डिवीजन का कारपोरेशन-फैजाबाद डिवीजन का कारपोरेशन, गोरखपुर डिवीजन का कारपोरेशन बना है। फिर जो बिजली का ढांचा है उसे मजबूत किया जा रहा है। बिजली के ढांचे को मजबूत करने के लिए—जनाव गौर फरमायें—सिंगरोली का एक बड़ा थर्मल स्टेशन, जो दोहजार मैग्नाट का है, वह पूर्वी यू० पी० में ही बन रहा है, मिर्जापुर में ओवारा में बन रहा है। मैं उनमें अदब के साथ कहूँगा कि मैं मोहतरीम मैम्बर की कद्र करता हूँ और वे इस बारे में और भी व्योरा जाना चाहेंगे तो मैं वह व्योरा हुजिर कर सकता हूँ।

लेकिन जहाँ तक छठी योजना का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको जिलेवार और इलाकावार बना रही है। आप इस बात को मंजूर करेंगे कि जहाँ हमारा काम, मरकजी हुकूमत का काम बड़े-बड़े 6500 करोड़ वाले

इस को मंजूर करना है, वहां ब्यौरेवार मंसुबा सूबाई सरकार ही बना सकती है। मैं समझता हूं कि वह इस बारे में मुझ से सहमत होंगे।

श्री संयद अहमद हाशमी : जनावेआली, मैं आप के विचारों की कद्र करते हुए भी इस बात पर अपने पूरे इतिमान का इजहार नहीं कर सकता क्योंकि इस के लिये आप ने कुछ आंकड़े दिये, लेकिन इंडस्ट्रीज की साइड को अगर आप देखें तो आप ने नंदगंज का हवाला दिया। वहां एक शुगर फैक्ट्री बनी है लेकिन उस का कोई कांट्रीब्यूशन नहीं है और कोई दूसरी फैक्ट्री उधर नहीं आयी है। लेकिन मैं आप के माध्यम से एक चीज का और मंत्री जी से जिक्र करना चाहता हूं, खासकर मरकजी सरकार का कि वहां गाजीपुर जिले में एक फैक्ट्री थी, जो इस नेशनल गर्वनमेंट का अहसान नहीं है, बल्कि अप्रेंजों के जमाने से वह फैक्ट्री वहां चली आ रही है और वहां के मजदूरों की स्ट्रेथ है हजार या डेढ़ हजार। लेकिन आज उस फैक्ट्री को बंद किया जा रहा है और उस को उठा कर नीमच ले जाया जा रहा है और ऐसा होने से जो वहां बेरोजगारों की लिस्ट रोज बड़ती चली जा रही है उस में मैं समझता हूं कि इस से बहुत ज्यादा सुधार नहीं होगा। आप की इस ओपियम फैक्ट्री के हट जाने से वहां की हालत में ज्यादा सुधार नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मरकजी हुक्मत की इस तरफ कोई तवज्ज्ञ है कि अगर उस इलाके में कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है तो उस को बड़ाया जाये, उस में मेडिसिन बनाने और दूसरी मुख्तलिफ किस्म की चीजें और शामिल की जा सकती हैं, कारखाने और बन सकते हैं क्योंकि वहीं पर ओपियम भी पैदा होता है, लेकिन इस के बावजूद उस फैक्ट्री को वहां से उठा कर ले जाया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस किस्म की हमदर्दी है कि वहां जो चीज पहले से है उस को भी वहा से उखाड़ा जा रहा है?

श्री मारायण दत्त तिवारी : मैं मोहतरिम मेम्बर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक गाजीपुर से ओपियम फैक्ट्री को नीमच ले जाने का सवाल है, इस की जानकारी मुझे नहीं है और न इस तरह की किसी फैक्ट्री का किसी जगह से हटाये जाने का योजना से संबंध रहता है। लेकिन अगर मोहतरिम मेम्बर चाहेंगे तो मैं इस संबंध में जानकारी करा लूंगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : माननीय मंत्री जी वडे विद्वान और योग्य व्यक्ति हैं।

श्री समाप्ति : जल्दी करिये।

श्री भा० दे० खोबरागढ़े : मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप ने शारदा प्रोजेक्ट की बात कही। घाघरा का पानी शारदा में डाल कर आप ने मध्य उत्तर प्रदेश को दिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश को नहीं दिया यह भारी बेर्इमानी हुई है उत्तर प्रदेश के साथ। आप गोलमटोल जवाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जो बेइसाकी हुई है उस को छिपाने की कोशिश मत करिये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने 12 पावर प्रोजेक्ट समिट किये और आज तक आप ने केवल तीन को स्वीकार किया है और 9 को आप ने फाइल में दबा कर रखा हुआ है। आप कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। मंत्री महोदय आप वहां की हालात से ज्यादा वाकिफ है। दस लाख ग्रोव मजदूर हर साल वहां से भाग कर पंजाब और हरियाणा आते हैं मजदूरी करने के लिये। यह हालत वहां की है। श्रीमन् भाखड़ा नंगल बनाया गया, लेकिन घाघरा की बाढ़ को रोकने के लिये आज आजादी के तीस साल हो गये, कोई उपाय केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया और अब उस की कोशिश हो रही है। श्रीमन् पटेल आयोग की रिपोर्ट को आज तक इंस्ट्रीमेंट नहीं किया गया। आप कहते हैं कि हम ने वहां के लिये 6ठी पंचवर्षीय योजना में सद से बड़ा एमाउंट

सेवकार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आज भी रो रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार उन को स्पष्ट नहीं दे रही है और उन के प्रोजेक्ट नहीं स्वीकार कर रही है। इसलिये मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश के जो पावर प्रोजेक्ट समिट हुए हैं 12, उन को आप कब तक स्वीकार करेंगे। नम्बर एक। और नम्बर दो यह कि धाघर की बाढ़ को रोकने के लिये आप कोई प्रोजेक्ट स्वीकार करेंगे या नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, विडान सदस्य ने यह कहा कि शारदा सहायक योजना से पूर्वी अंचल को लाभ नहीं हुआ। इतना समय नहीं है कि इसके विस्तार में जा सकूँ, लेकिन उनको अलग से भी हैं यह सूचना दे सकता है कि शारदा सहायक योजना से मुख्यतया पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही जिलों को लाभ हुआ है। एम०पी० के दो एक जिले हैं। लेकिन उनको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी शारदा सहायक योजना के दूसरे चरण से बहराइच, गोडा, बस्ती और उनके पिछड़े हुए जिले गोरखपुर को लाभ हुआ है।

श्री नागेश्वर प्रताद शाही : वह अभी शुरू हुई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वह पांचवी योजना से शुरू हो गया है। श्रीमन्, वह स्वीकार कर रहे हैं कि हुआ है। अब गंडक योजना शुरू हुई है। बाकी जो उन्होंने कहा है कि 12 पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो स्वीकार किये जाने हैं, उनमें से कई स्वीकार हो चुके हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : केवल तीन हुए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : कौन से नहीं हुए हैं? श्रीमन्, 12 जो उन्होंने बताया इनमें से कुछ हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं। जहां तक पूर्वांचल का सवाल है उनको स्वीकार किया जा चुका है। इनमें ऊंचाहार और सिंगोली की

योजनायें स्वीकार हो चुकी हैं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दूँ कि केवल प्लानिंग कमीशन इसमें अंतिम निर्णय नहीं लेता। पहले ऊर्जा मंत्रालय को निर्णय लेना होता है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की दूसरी योजनाओं के सम्बन्ध में, दूसरे प्रोजेक्ट्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में अपनी ओर से जहां तक हो सकेगा, हम सहानुभूतिपूर्ण निर्णय ले सकेंगे।

डा० रुद्र प्रसाद सिंह : मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर में अमेठी संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्या मंत्री जी अपनी योजना को बनाते समय अमेठी निर्वाचन क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ध्यान रखने की कृपा करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Implementation of the recommendations made by General Purposes Sub-Committee of E.S.I.

***42. PROF. RAMLAL PARikh:** Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 1423 given in the Rajya Sabha on the 4th December, 1980 and state:

(a) what action has been taken by the Government of Gujarat on each of the recommendations of the General Purposes Sub-Committee of the E.S.I. Scheme;

(b) what is the extent of the Central Government's responsibility in